SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

पर्यावरणीय विकास एवं राजनीति : छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक अध्ययन

मणिमेखला शुक्ला, (Ph.D.) राजनीति शास्त्र विभाग
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
मणिमेखला शुक्ला (Ph.D.)

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 03/04/2023
Plagiarism : 00% on 27/03/2023

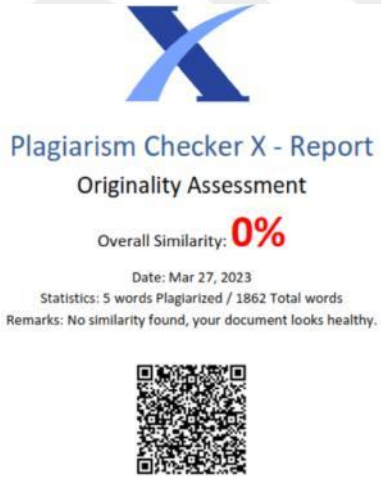

शोध सार

पर्यावरण, यातायात एवं व्यवसायिक क्रियाओं को प्रसारित होने का अवसर किसी भी राज्य की राजनीतिक स्थायित्व से प्राप्त होता है, क्योंकि इससे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण निर्मित होता है। इस प्रकार पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा राजनीतिक स्थायित्व में घनिष्ठ संबंध होता है। राजनीतिक स्थिरता प्रभावपूर्ण नियोजन, प्रबंधन एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण घटक है। राजनीति का प्रभाव व्यापक होता है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पर्यावरण ही नहीं अपितु प्रत्येक क्षेत्र में अपनाई गई नीतियों का राज्य के बहुआयामी विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण अब राज्य स्तर के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संबंधों का एक प्रमुख तत्व है। यह राजनयिक हलकों में उच्च प्राथमिकता रखता है। पर्यावरणीय मामले समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं उनके अकादमिक अध्ययन के लिये केन्द्रीय विषयवस्तु बन गये हैं क्योंकि इसने प्रत्येक स्तर पर शासन की रचना, विभिन्न राजनीतिक नीतियों के अनुपालन एवं वित्त पोषण तंत्र के तकनीकी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया है।

मुख्य शब्द

राजनीतिक स्थिरता, प्रभावपूर्ण नियोजन, बहुआयामी विकास, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अकादमिक अध्ययन.

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ सरकार और राजनीति ने भारत के राजनीतिक इतिहास में कुछ नए अध्याय जोड़े हैं। हालाँकि, मध्य प्रदेश के बड़े राज्य का विभाजन और छत्तीसगढ़ का जन्म काफी शांतिपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक एवं जातीय पहचान को संरक्षित करने के लिए एक राज्य की माँग ने भारत के

इतिहास में कुछ नए अध्यायों को जन्म दिया। इसने इस नए राज्य के गठन को पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है। राज्य में प्रमुख राजनीतिक दलों का पर्यावरणीय विकास के प्रति सदैव सकारात्मक प्रयास रहा है। यहां की राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध खनिज, वन एवं अन्य नैसर्गिक संसाधनों को स्वपोषित निरंतरता के साथ राज्य के हित में उपयोग करना है। स्वपोषित एवं शाश्वत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को भी बराबर महत्व देता है एवं इस क्षेत्र में राजनीतिक नीतियों के महत्व को कम नहीं समझा जा सकता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश की पर्यावरण नीति सामाजिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार रणनीतियों का निर्धारण किया गया है जो कि राज्य स्तरीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है:

1. पर्यावरण आधारित संसाधन नियोजन।
2. सहभागी प्रबंधन एवं बाजार आधारित प्रक्रिया का निर्धारण।
3. जन सहयोग द्वारा सकारात्मक क्रियान्वयन।

प्रदेश स्तरीय राजनीति का एक प्रमुख बिंदु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005 है, जिसे दिनांक 27/05/2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं को लागू करने के लिये धन जुटाने हेतु भूमि पर उपकर लगाना था। एक अन्य सराहनीय कदम 28 नवंबर 2017 को उठाया गया जब छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत पर्यावरण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के 6 बड़े शहरों रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा में दिसंबर एवं जनवरी माह में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदूषण पर राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति है। पिछले 5 वर्षों से किये जा रहे इस प्रयास के फलस्वरूप रायपुर शहर के प्रदूषण स्तर में काफी सुधार हुआ है एवं वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है। सकारात्मक राजनीतिक प्रयासों एवं शासन की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण सक्रियता से ही प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों में सफलता संभव है।

उद्देश्य

1. पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में छ.ग. सरकार की नीतियों का अध्ययन करना।
2. पर्यावरण आधारित संसाधन नियोजन में छ.ग. सरकार की नीतियों का अध्ययन करना।

छ.ग. सरकार की पर्यावरणीय चेतना की दिशा में सार्थक पहल

कांग्रेस के वर्तमान शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा पुनर्याजी विकास (रिजनरेटिव डेव्हलपमेंट) की अवधारणा को नवीन दिशा प्रदान करने एवं छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य ग्रीन काऊंसिल का निर्माण प्रस्तावित किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल जी की अध्यक्षता एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा की उपाध्यक्षता वाले इस छत्तीसगढ़ राजय ग्रीन काऊंसिल में 12 सदस्यों की नियुक्ति प्रस्तावित है। निरंतर पर्यावरणीय क्षरण के कारण विश्व स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन एवं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के दुष्परिणामों से बचने के लिये पुनर्याजी एवं सतत् विकास ही एकमात्र विकल्प है जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति की रक्षा के साथ–साथ साधनहीन समुदायों की आय में वृद्धि एवं कृषि के क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित हो सकेगी। इस दिशा में सकारात्मक राजनीतिक प्रयास के रूप में यह कदम सराहनीय प्रतीत होता है जिसका परिणाम भविष्य में अवश्य परिलक्षित होगा।

वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी सरकार के खाते में कई उपलब्धियाँ हैं। इंडिया टुडे द्वारा किये गए सर्वे में छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में बेस्ट परफोर्मिंग स्टेट में दूसरे

स्थान पर तथा मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट की श्रेणी में पहले स्थान पर बाजी मारी है। यह सर्वे SO_2, NO_2 और पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सघनता और वन आवरण जैसे विभिन्न मापदंडों पर आधारित है। सर्वे में प्रतिवेदित है कि छत्तीसगढ़ ने पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न सुधारात्मक कार्य कर एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क और डोलोमाइट के उत्पादन से खनिज आधारित उद्योगों का प्रसार हुआ है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि हुई है लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना किया है। चार सालों में राज्य में 18 नए परिवेषी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों की वजह से SO_2 सांद्रता 2016 में 26.02 से गिरकर 2020 में 16.34 हो गई है, जो कि 37 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, NO_2 की सांद्रता 24.11 से घटकर 19.88 हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सात प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 27 स्टेशन स्थापित किए हैं। शहरी केंद्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए मिशन क्लीन सिटी या 'अंबिकापुर मॉडल' को पूरे राज्य में लागू किया गया है। पर्यावरण संवर्धन के लिए राज्य ने औद्योगिक क्षेत्र के 30 प्रतिशत में वृक्षारोपण अनिवार्य किया है। 2015 और 2019 के बीच, वन आवरण 41.12 प्रतिशत से बढ़कर 41.14 प्रतिशत हो गया, और वृक्ष आच्छादन 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया।

छत्तीसगढ़ वायु, जल प्रदूषण, ठोस कचरे के प्रबंधन और वनों के संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए वर्ष 2021 में पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2018 में 17वें, वर्ष 2019 में 6वें तथा वर्ष 2020 में दूसरे पायदान पर रहते हुए वर्ष 2021 में पहले पायदान पर है। इसी तरह इंडिया स्टेट ऑफ दी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोहा, कोयला, डोलोमाइट जैसे खनिजों से परिपूर्ण है, जिसके कारण राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार हुआ है। इन उद्योगों की स्थापना से एक ओर जहाँ क्षेत्र के लोगों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है, वहीं इसके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट की चुनौतियाँ भी मिल रही हैं।
- राज्य सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता जाँचने के लिये 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किये गए हैं।
- वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित तीन प्रमुख नगर निगमों–रायपुर, भिलाई, कोरबा में राष्ट्रीय साफ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं। वायु में सल्फर की मात्रा 37 प्रतिशत तक कम हो गई है। यह 2016 में 26.02 माइक्रोग्राम थी, जो 2020 में घटकर 16.34 माइक्रोग्राम हो गई।
- इसी प्रकार दैनिक नाइट्रोजन डाईऑक्साइड संकेंद्रण में भी 17 प्रतिशत की कमी आई है। यह 24.11 माइक्रोग्राम से घटकर 19.88 माइक्रोग्राम रह गई है।
- इसी तरह राज्य सरकार ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत राज्य की 7 प्रमुख नदियों में पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिये 27 स्टेशन स्थापित किये हैं। इनमें 5 प्रमुख नदियों–खारून, महानदी, हसदेव, केलो और शिवनाथ का पानी पीने योग्य पाया गया है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिये 10 स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
- छत्तीसगढ़ की लगभग 28.8 मिलियन आबादी में 6 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों से लगभग एक हजार 650 टन ठोस कचरा प्रतिदिन एकत्र होता है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिशन क्लीन सिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
- अंबिकापुर में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट पृथक्करण और रिसाइकिलिंग मॉडल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में भी हानिकारक कचरे के निपटान के लिये अलग से सुविधाएँ विकसित की गई हैं। इसी प्रकार बायोमेडिकल कचरे के निपटान के लिये 4 यूनिट भी प्रस्तावित हैं।

- हाल ही में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छतम राज्य के रूप में सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ लगातार तीन सालों से देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है।
- छत्तीसगढ़ राज्य 44 प्रतिशत वनों से आच्छादित है, इससे ग्रीन हाउस के प्रभावों को भी कम करने में मदद मिल रही है, वहीं सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया के 30 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण अनिवार्य किया गया है।

पिछले दिनों हसदेव अरण्य देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। प्रमुख मुद्दा पर्यावरण संपदाओं से संपन्न इस वन–क्षेत्र में वनों की कटाई एवं खनन था। सोशल मीडिया पर मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने तथा प्रकृति माँ की उजड़ी हुई गोद की हृदयविदारक तस्वीरों के फैलने के बाद ग्रामीणों समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रकृति प्रेमी संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की समृद्धि, पर्यावरणीय महत्व एवं उसकी आवश्यकता को समझने के बाद भी केन्द्र एवं राज्य सरकार ने खनन की अनुमति प्रदान की एवं 6 हजार एकड़ क्षेत्रफल में 4 लाख 50 हजार पेड़ों का काटा जाना निश्चित किया गया।

निष्कर्ष

पर्यावरण एवं राजनीति का सदैव ही घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्तमान समय में यह संबंध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई परिभाषा लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन दोनों का आपसी सामंजस्य ही देश की उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा सुनिश्चित करेगा। छत्तीसगढ़ की वन संपदा, उद्योग, यातायात, व्यापार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के राजनीति के साथ सकारात्मक तालमेल से ही यह संभव है। राज्य के स्थापना दिवस से ही सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में उठाये गये कदम सराहनीय हैं जिन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये भविष्य में निश्चित ही नवीन नीतियाँ तैयार होंगी जो राज्य के समग्र विकास एवं संपन्नता में सहायक सिद्ध होंगी।

संदर्भ सूची

01. मुखर्जी अंजू, *पर्यावरण परिचय,* छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, 2007।
02. कुमार प्रदीप, *पर्यावरण प्रदूषण,* डिस्कवरी पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2007।
03. राजशेखर ए., *पर्यावरण अध्ययन,* दिव्या प्रकाशन, रायपुर।
04. कुमार मनोज, *पर्यावरण संरक्षण,* कुनाल प्रकाशन, दिल्ली, 2006।
05. मार्कण्डेय दिलीप कुमार एवं राजवैद्य नीलिमा, *प्रकृति, पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण,* ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, 1999।
06. शुक्ला प्रदीप एवं पाण्डेय सीमा, *छत्तीसगढ़ में पर्यटन,* वैभव प्रकाशन, रायपुर।
07. गुप्ता जया, छत्तीसगढ़ का भौगौलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिचय. Int- J- Rev- and Res- Social Sci- 2019; 7(1): 239-250.

****